



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1936 (श0)

(सं0 पटना 896) पटना, शुक्रवार, 7 नवम्बर 2014

सं0 2ब0/13वें वित्त 25-02/2014-3253/न0 वि0 एवं आ0 वि0  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 अक्टूबर 2014

**विषय:-** 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय के प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

13वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान की राशि भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को विमुक्त की जाती है तथा वित्त विभाग से राशि विमुक्ति की सूचना प्राप्त होने पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर राशि वितरित की जाती है।

2. 13वीं वित्त आयोग की राशि से वर्तमान में निम्नांकित कार्य कराने का प्रावधान किया गया है:-

(क) कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,

(ख) पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रख-रखाव सहित,

(ग) सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेय जल पर उपभोग किये गये बिजली के बिल का भुगतान,

(घ) रैन बसेरा/Old Age Home का निर्माण एवं रख-रखाव।

3. नगर निकायों के साथ समीक्षात्मक बैठकों में यह तथ्य सामने आया है कि 13वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग उपर्युक्त योजनाओं में निम्न कारणों से नहीं हो पा रहा है :-

(i) कई नगर निकायों में पाईप जलापूर्ति व्यवस्था नहीं है तथा नगर निकायों के पास पाईप जलापूर्ति अधिष्ठापित करने के लिए अभियंता आदि भी नहीं हैं,

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रावधानित राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है,

(iii) रैन बसेरा निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि के व्यय हेतु पूर्व में किये गये प्रावधानों में संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये जाते हैं :-

(i) **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** - उपकरणों के क्रय, उपकरणों को रखने हेतु शेड के निर्माण, सफाई हेतु मजदूरी के भुगतान, ट्रैक्टर के भाड़ा भुगतान, Out Sourcing के माध्यम से सफाई हेतु एजेंसी के भुगतान आदि पर 40-50 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(ii) **जलापूर्ति** - पाईप जलापूर्ति, Submersible Pump के माध्यम से जलापूर्ति तथा चापाकल के माध्यम से जलापूर्ति पर 10-20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(iii) **स्ट्रीट लाईट** – हाई मास्ट लाईट/स्ट्रीट लाईट लगाने, उसके रख-रखाव तथा बिजली बिल के भुगतान पर 10 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जाये।

(iv) **रैन बसेरा** – रैन बसेरा/ Old Age Home के निर्माण एवं रख-रखाव पर 10-20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

(v) **नाला निर्माण** – नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण पर 10-20 प्रतिशत राशि का व्यय किया जाये।

5. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.10.2014 के मद संख्या 04 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 896-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>